vinetur

फ्रांस 2027 और 2028 में किसानों को उसी साल की आय के आधार पर सामाजिक अंशदान देने की अनुमति देगा

पात्र MSA सदस्य 1 अक्टूबर से 31 मार्च 2027 तक अपने व्यक्तिगत खाते से प्रायोगिक विकल्प चुन सकते हैं

गुरुवार, 12 नवंबर 2026



फ्रांस की कृषि सामाजिक सुरक्षा प्रणाली MSA के दायरे में आने वाले किसान 2027 और 2028 में एक प्रायोगिक तरीका चुन सकेंगे। इसके तहत सामाजिक अंशदान की गणना उसी साल अर्जित आय पर होगी, न कि केवल पिछले साल की आय या तीन साल के औसत पर। इस बदलाव का उद्देश्य अंशदान भुगतान को कारोबार की मौजूदा स्थिति के अनुरूप बनाना और कुछ मामलों में नकदी प्रवाह पर दबाव कम करना है।

यह नया विकल्प फ्रांस के 2026 सामाजिक सुरक्षा वित्तपोषण कानून के तहत बनाया गया और 24 सितंबर को जारी कार्यान्वयन आदेश के बाद लागू हुआ। Réussir में बुधवार, 11 नवंबर को प्रकाशित एक साक्षात्कार में, Cogedis में कृषि

कर और सामाजिक मामलों की प्रमुख Gaëlle Le Peltier ने कहा कि किसान 1 अक्टूबर से 31 मार्च 2027 तक अपने व्यक्तिगत MSA खाते के ज़रिए यह विकल्प सक्रिय कर सकते हैं।

अब तक, स्व-रोज़गार करने वाले किसानों के पास अंशदान की गणना के लिए आम तौर पर दो विकल्प थे : पिछले साल की आय, जिसे N-1 कहा जाता है, या N-1, N-2 और N-3 को शामिल करने वाला तीन साल का औसत। नया प्रायोगिक विकल्प तीसरी संभावना जोड़ता है, जिसे N यानी मौजूदा साल कहा जाता है। इस व्यवस्था में किसान उसी साल की अनुमानित आय के आधार पर अस्थायी रूप से अंशदान देते हैं, जिस साल भुगतान देय होता है।

यह विकल्प MSA सदस्यों के लिए उपलब्ध है, चाहे वे फिलहाल पिछले साल वाली पद्धति अपनाते हों या तीन साल का औसत, बशर्ते उनके अंशदान वास्तविक आय पर आधारित हों, न कि एकमुश्त निर्धारित आधार पर। इसका अर्थ है कि एकमुश्त दरों के नियमों के तहत आने वाले कुछ नए किसान इसके पात्र नहीं होंगे।

विकल्प चुनते समय खेत के संचालक को 2027 की अनुमानित आय घोषित करनी होगी। Réussir की रिपोर्ट के अनुसार, यह अनुमान न्यूनतम अंशदान से जुड़ी आय के स्तर से कम और वार्षिक सामाजिक सुरक्षा सीमा से अधिक नहीं हो सकता। इस तरह सीमा €8,300 से €48,900 के बीच होगी। इसके बाद इसी अनुमान के आधार पर मासिक या किस्तों में अस्थायी अंशदान मांग जारी की जाएगी। अंतिम समायोजन 2028 की गर्मियों में होगा, जब किसान मई 2028 में 2027 की आय का विवरण दाखिल कर देगा।

Le Peltier ने कहा कि किसान विकल्प चुनने के लिए फरवरी 2027 तक इंतज़ार करने पर विचार कर सकते हैं, क्योंकि तब उन्हें बाज़ार की स्थितियों और आने वाले महीनों की संभावित कमाई की अधिक स्पष्ट तस्वीर मिलेगी। रिपोर्ट के मुताबिक, अनुमान बाद में अंतिम नतीजे से काफी अलग साबित हो, तब भी इस अंतर के कारण कोई जुर्माना या अधिभार नहीं लगेगा।

यह विकल्प हर साल अलग से चुना जाता है। इसका नवीनीकरण अपने आप नहीं होता, लेकिन एक बार चुने जाने के बाद उस साल इसे बदला नहीं जा सकता। अगले साल किसान प्रयोग से पहले वाली व्यवस्था पर लौट सकता है या मौजूदा साल वाला विकल्प दोबारा चुन सकता है। मौजूदा नियमों के अनुसार, यह परीक्षण केवल 2027 और 2028 के अंशदान पर लागू होगा।

इस उपाय के समर्थक इसे मुख्य रूप से नकदी प्रवाह के प्रबंधन का साधन मानते हैं। इसका तर्क यह है कि मौजूदा आय कमज़ोर होने पर किसी खेत को पहले के वर्षों की अधिक आय के आधार पर अंशदान देना जारी नहीं रखना पड़ेगा। यह उन क्षेत्रों के लिए अहम हो सकता है जहां एक मौसम से दूसरे मौसम में नतीजे काफी बदलते हैं। पेय उद्योग में यह उपाय अंगूर उत्पादकों के लिए विशेष रूप से प्रासंगिक हो सकता है, क्योंकि उनके सामाजिक अंशदान मौजूदा फसल वर्ष की आय के अनुरूप बेहतर ढंग से तय हो सकते हैं। इससे बेहतर विंटेज के बाद उत्पादन या बिक्री घटने पर नकदी पर दबाव कम हो सकता है।

हालांकि, हर मामले में इसका लाभ एक जैसा नहीं होगा। Réussir की रिपोर्ट के अनुसार, यह व्यवस्था वार्षिक सामाजिक सुरक्षा सीमा के बराबर या उससे कम अनुमानित आय के लिए सबसे सीधे तौर पर काम करती है, क्योंकि अस्थायी अंशदान मांग मोटे तौर पर अंतिम देय राशि के अनुरूप होगी। इस सीमा से अधिक आय होने पर किसान को 2028 की गर्मियों से बकाया राशि का हिसाब फिर भी देना होगा।

Le Peltier ने कहा कि यह विकल्प उन खेतों के लिए सबसे आकर्षक हो सकता है जिनका लेखा वर्ष की पहली छमाही में बंद होता है, जिन्होंने 2025-2026 में अच्छे नतीजे दर्ज किए, लेकिन 2027 में कम आय की उम्मीद है। ऐसी स्थिति में मौजूदा साल के आधार से पहले की अधिक आय अंशदान की गणना में बनी नहीं रहेगी। जिन खेतों का लेखा वर्ष की अंतिम तिमाही में बंद होता है, उनके लिए फैसला करना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि 31 मार्च 2027 की समयसीमा तक उन्हें सालाना नतीजे का कम अंदाज़ा होगा।

यह नया तंत्र फ्रांस की मौजूदा व्यवस्था से अलग है, जिसके तहत किसान अग्रिम भुगतानों में बदलाव कर सकते हैं। उस पुराने विकल्प में वे किस्तों को समायोजित करने के लिए सालाना अनुमानित आय बता सकते हैं और कमाई में बड़ा बदलाव होने पर साल के अंत में भारी बकाया से बच सकते हैं। लेकिन इससे अंशदान की गणना का कानूनी आधार नहीं बदलता। नया N-वर्ष विकल्प ऐसा करता है।

इस उपाय के कर संबंधी प्रभाव भी हैं। micro-BA व्यवस्था के तहत आने वाले खेतों के लिए Le Peltier ने कहा कि इसका कोई कर प्रभाव नहीं होगा। वास्तविक कृषि लाभ पर कर देने वाले खेतों के लिए सामाजिक अंशदान कम होने से कर योग्य आय यांत्रिक रूप से बढ़ जाएगी। साक्षात्कार के अनुसार, कई किसानों के पास फिर भी खर्च करने योग्य अधिक आय बच सकती है, क्योंकि आयकर की दरें अक्सर सामाजिक अंशदान की दरों से कम होती हैं। इसके बावजूद, कर योग्य आय बढ़ने से कुछ परिवार पारिवारिक लाभ या अन्य सामाजिक सहायता के लिए तय सीमा से ऊपर जा सकते हैं। इसी वजह से सलाहकार किसानों को फैसला करने से पहले गणना करने की सलाह दे रहे हैं।

यही सावधानी फ्रांस की एहतियाती बचत कटौती पर भी लागू होती है, जिसे DEP कहा जाता है। Réussir की रिपोर्ट के अनुसार, जो किसान फिलहाल पिछले साल वाली पद्धति के तहत हैं और 2027 में मौजूदा साल के आधार पर आते हैं, उन्हें 2026 की आय पर सामाजिक अंशदान नहीं देना होगा। इसलिए कर योग्य आय में वापस जोड़ी गई DEP की राशि उस साल के सामाजिक अंशदान के आधार में अपने आप शामिल नहीं होगी।

प्रकाशन में दिए गए एक उदाहरण से पता चला कि यह विकल्प भुगतान के समय को कैसे बदल सकता है। एक खेत की आय 2025-2026 में €70,000 थी और फिर 2026-2027 में घटकर €40,000 रह गई। पिछले साल वाली पद्धति के तहत 2027 में भी अधिक आय के आंकड़े पर अंशदान देना जारी रहता, जबकि प्रायोगिक मौजूदा साल की पद्धति से 2027 के अंशदान का आधार कहीं पहले घटकर €40,000 के नतीजे के अनुरूप हो जाता।